THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMAT1 JAYANTHI NATRAJAN): This is a matter relating to the State. How can you raise it here?

SHRI KHYOMO LOTHA: T have the permission of the Chairman.

When the Governor has already summoned a one-day session of the Assembly on 7th~notice was issued on the 2nd August-the Chief Minister had forced the Governor to induct two more Ministers on the 3rd of August.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): He cannot raise this isssue in this manner.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): He has got the permission of the Deputy Chairman to raise this issue. Let me read it:

"Induction of two Ministers in the Meghalaya Cabinet after issuing summons of the special session of the Assembly." My hands are tied.

SHRI KHYOMO LOTHA: How can the swearing in take place when the Government is required to prove its majority? The question is whether the Governor is forced and, if so, under what circumstances. It is just to induce the Members to vote for the Government that the new Ministers have been inducted. This is corruption. Also, there was delay of 90 minutes. If the Members were willing to become Ministers, why this delay in swearimg-in? These things have to be looked into by the Government.

SHRI G. G. SWELL (Meghalaya): Induction of Ministers into the Cabinet and the Governor acting on it is purely his own judgement. I see no point in raising this question before this House.

Need for Regular supply of coal from Western coalfields Ltd. to Industries in Maharashtra and Madbya Pradesh

श्री नरेश पुगलिया (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का तथा कोयला मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि विदर्भ तथा पूर्ण महाराष्ट्र वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की ओर से जो कोयले की पूर्ति की जाती थी, यह 90 परसेंट इंडस्ट्रीज का रा-मेटिरियल है, लेकिन हाल ही में जून महीने से उनको कोयले की पूर्ति बन्द कर दी गई है। मेजर प्लांट, मिडीयम प्लांट और मिनी प्लांट का 70 परसेंट कोयले का कोटा काटल किया है और उनको 30 परसेंट तथा सीमेंट प्लांट को 45 परसेंट कोयला दिया जा रहा है और वह कोयला डब्ल्यू सी एल के एरिये से न देते हुये, उसको ई सी सी एल० से दिया जा रहा है। इ०सी०सी०एल० विदर्भ और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश से काफी दूर है। 700 किलोमीटर से वहां पर कोयला लाना पड़ता है उससे कोयले की ट्रांसपोर्टेशन कास्ट 700—800 रुपये प्रति टन बढ़ रही है और इससे महाराष्ट्र और विदर्भ तथा मध्य प्रदेश की कुछ इंडस्ट्रीज बन्द होने के रास्ते पर हैं और इससे लाखों मजदूर बेकार होने जा रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार का इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बकस्टाक में लाखों टन कोयला स्टाक में बताया गया है। बुक स्टाक में जब कोयला उपलब्ध है तो ऐसी हालत में हर बारिश के अन्दर, इस प्रकार से पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि बारिश के समय वह लोग कोल की इंडस्ट्रीज को सप्लाई बन्द कर देते हैं और ओपन मार्केट में नागपुर, चन्द्रपुर आप कहीं भी जाइये, ग्यारह सौ रुपये प्रति टन ब्लैक में कोयला हजारों टन की मात्रा में उपलब्ध है। एक तरफ ब्लैक में कोयला मिलता है और दूसरी तरफ यह कोयला कम्पनीज

[श्री नरेश पुगलिया]

हैं इन्होंने इंडस्ट्रीज को कोयला देना बन्द किया है और इनका कहना है कि साऊथ में एन टी पी सी का जो हमारा सिगरैनी प्रोजेक्ट है उसके लिये और साउथ की जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसके लिये हम कोल सप्लाई कर रहे हैं। अगर वहां कोल की कमी है तो इ सी सी एल० से डायरेक्ट वहां कोल भेज सकते हैं। इ सी सी०एल० से डब्ल्यू सी एल में जो लोग वहां कोल लिंकेज के होल्डर्स हैं उनको वहां से कोयला नहीं देते और सात सौ किलोमीटर से कोयला लाना, यह कहां की अक्लमन्दी है? इस कारण महाराष्ट्र के कई प्लांट बन्द होने जा रहे हैं। उन्होंने वर्कर्स को इस प्रकार से क्लोजर की नोटिस दी है और यह चिंता का विषय बना हुआ है।

आपके माध्यम से मैं कोल मिनिस्टर को कहना चाहूंगा कि इसकी आप जांच करें और कोल इंवेंट्री को इमीडिएट वहां जाकर स्टाक की जांच करने के लिये भेजें और जो इंडस्ट्री बन्द होने के कारण लाखों मजदूर बेकार होने जा रहे हैं और इसके कारण जो अशांति फैलेगी, इस ओर केन्द्र सरकार ध्यान दे। मैं उम्मीद करता हूं कि सदन के नेता यह भी महाराष्ट्र से आते हैं, इसमें कोल की आर्टिफिशयल शोर्टेज को वेस्टन कोल फील्ड्स और कोल इंडिया कर रहे हैं, इसमें आप तुरन्त ध्यान दें और इंडस्ट्रीज को तुरन्त कोयला सप्लाई करें, क्योंकि मंत्री महोदय ने इसी राज्य सभा में कहा था कि हम कम से कम जो कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में आती हैं, उसको 100 परसेंट कोयला दे रहे हैं, लेकिन उसका भी उन्होंने सिर्फ 45 परसेंट वह भी सात सौ किलोमीटर दूर से लाने के लिये कहा है। इस प्रकार से इनजस्टिस हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें सदन के नेता हस्तक्षेप करेंगे और जल्द से जल्द कोयला उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

SHRI JAGESH DESAI (Maharshtra) Madam, this is a very serious matter. If coal is not supplied in time and in full quantity, the industries would not be able to exploit their resources and use their capacity to the full. This will again rise the prices Ultimately, the consumer will have to pay the price because of non-supply of coal. As such, it is in the interest of the industries, the workers and also the consumers that adequate quantity of coal is supplied. If coal is not supplied to the cement industry, the cement production would go down. If the cement production goes down, housing activity would be affected. Prices would go up. Therefore, to bring down the prices, it is necessary that coal is supplied in full quantity and in time so that the industries can work to their full capacity

1 would request the hon. Minister of Coal to see that the industries in Maha- rashtra are supplied coal, not from a far off place as that would again add to the price, but from the nearest coalfield, so that the price is kept down.

Loss of human lives, iivestock and property perry due to unprecedented heavy rains in Orissa

SHRI SARDA MOHANTY (Orissa): Madam Vice-Chairman, due to the low pressure in the Bay of Bengal, there was a unprecedented heavy downpour in the Southern and coastal districts of Orissa causing sudden and unexpected floods in almost all the rivers of Orissa. more particularly, in the river Indravati.

Almost all the 13 districts of Orissa have been affected by the heavy rain and floods of July last.

People could not come out from their thouses to attend to their day-to-day work and earn their livelihood. Livestock could not be fed. Village roads were submerged either by rain or flood waters. Communications were almost disrupted. River embankments were damaged by breaches. Highways including National Highways were either washed away or cut off resulting in big ditches. The communication system was disrupted in such a way that it was not possible to ply relief vehicles to the marooned areas and also to the district headquarters. Transport services totally stopped. Correct information could